पीएम मोदी के मंत्र से यूपी में विकसित हुआ उद्योगों का तंत्र

सीएम योगी ने नीति आयोग की बैठक में रखीं प्रदेश की उपलब्धियां ■ एमएसएमई, महिला सुरक्षा, ढांचागत विकास, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण के गिनाए काम

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के 'ड्रीम डेस्टिनेशन' के रूप में उभरा है। उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य और पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाईं।

योगी ने सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की दिशा व प्रगति को नीति आयोग के सामने रखा। सीएम ने कहा कि हम पंचप्रण के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। यूपी सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक है। अगले पांच वर्षों में यूपी ने 10 खरब डॉलर का योगदान देने का संकल्प लिया है। लखनऊ में फरवरी में यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 में आयोजित निवेश महाकुंभ में करीब 35 लाख करोड़ रुपये के 22,000 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इससे 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है।

नई दिल्ली में सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। -विज्ञप्ति

नई ऊंचाइयों पर ओडीओपी

सीएम ने कहा कि 96 लाख इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। ओडीओपी स्कीम के तहत हर जिले परंपरागत उत्पाद नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, सिटी डेवलपमेंट प्लान, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए करीब 40 विभागों के 4,094 अनुपालन कम किए गए। 577 मामले में अनुपालन को निरपराधीकरण श्रेणी के तहत कम किया गया। 947 अनुपयोगी अधिनियम, विनियम और नियम आदि समाप्त किए गए हैं।

15 लाख युवाओं को दिया प्रशिक्षण

योगी ने कहा कि 2022-23 तक करीब 15 लाख युवा प्रशिक्षित और 6 लाख से अधिक युवा सेवायोजित किए गए हैं। आईटीआई में ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण शुरू किया गया है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और एडवांस कम्प्यूटिंग पर छात्रों व प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का राष्ट्रीय औसत 63.3 प्रति लाख के सापेक्ष यूपी का मात्र 50.5 प्रति लाख, वर्तमान समय में प्रदेश में दोष सिद्धि का औसत राष्ट्रीय औसत से लगभग दो गुना है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 1,548 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित हैं।

सूक्ष्म उद्यमियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश सरकार ने प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन) योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में एमएसएमई पार्क विकसित करने के लिए निवेशकों को भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत, एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक नई दुर्घटना बीमा योजना शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।